



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बोरबार, 21 सितम्बर, 2000/30 चैत्रपद, 1922

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

विधायी (अंग्रेजी) शाखा

अधिसूचना

शिमला-2, 21 सितम्बर, 2000

संख्या एल० एल० आर०डी०(६)-१८/२०००-लेज०.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद २०० के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख १६-९-२००० को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश

साधारण विनय कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक संख्यांक 17) को 2000 के अधिनियम संख्यांक 21 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन उभक्त प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-  
सचिव (विधि)।

2000 का अधिनियम संख्या 21.

## हिमाचल प्रदेश साधारण विक्रय कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2000

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 16 सितम्बर, 2000 को यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश साधारण विक्रय कर अधिनियम, 1968 (1968 का 24) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश साधारण विक्रय कर संक्षिप्त नाम । (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2000 है ।

1968 का 24 2. हिमाचल प्रदेश साधारण विक्रय कर अधिनियम, 1968 (जिसे इसमें इसके धारा 4 का पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 4 में,— संशोधन ।

(i) उप-धारा (1) का लोप किया जाएगा; और

(ii) उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"प्रत्येक व्याहारी जो, धारा 7 के अधीन कर मुक्त घोषित किए गए माल में अन्य रूप से व्यवहार नहीं करता है, वह इस अधिनियम के अधीन उस तारीख से जिस पर, किसी भी वर्ष के दौरान उसके सकल आवृत कराधेय की मात्रा प्रथमतः अधिक होती है, कर सदन करने का दायी होगा ।"

3. मूल अधिनियम की धारा 6 में,—

धारा 6 का संशोधन ।

(i) उप-धारा (1) में प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु अनुसूची—'क' में यथा विनिर्दिष्ट माल के विक्रय पर कर, एक रुपए में बीस पैसे से अधिक ऐसी दर से, जैसी इस प्रकार अधिसूचित की जाए, उद्गृहीत किया जा सकेगा, सिवाय—

(क) चूना पत्थर जिस पर एक रुपए में सी पैसे से अधिक की दर पर कर ; और

(ख) मद्य (देसी मद्य, विदेशी मद्य और भारत में बनी विदेशी मद्य जिसके अन्तर्गत बीयर है किन्तु भारत में बनी साईडर तथा शराब इसके अन्तर्गत नहीं है), पोलीथीन बैगज और इमारती लकड़ी (किन्तु रूपान्तरित इमारती लकड़ी इसके अन्तर्गत नहीं है) जिन पर एक रुपए में तीस पैसे से अधिक की दर से कर उद्गृहीत किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसा करने के अपने आशय का तीस दिन से अन्यान का नोटिस देने के पश्चात् ऐसी ही अधिसूचना द्वारा, अनुसूची-"क" में किसी माल को जोड़ या उससे लोप कर सकेगी या अनुसूची को अन्यथा संशोधित कर सकेगी और तदुपरि अनुसूची तदनुसार संशोधित की गई समझी जाएगी :"; और

(ii) उप-धारा (3) के खण्ड (क) में, उप-खण्ड (iii) का लोप किया जाएगा।

धारा 7 का संशोधन। 4. मूल अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (2) में, "अनुसूची—"ख" में जोड़ सकेगी या उस में से लोप कर सकेगी" शब्दों और चिन्हों के स्थान पर, "किसी माल को अनुसूची "—ख" में जोड़ सकेगी या उस में से लोप कर सकेगी या अन्यथा अनुसूची को संशोधित कर सकेगी", शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

धारा 8 का संशोधन। 5. मूल अधिनियम की धारा 8 में, उप-धाराएं (2), (3), (4), (5) और (6) के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"(2) हिमाचल प्रदेश में विक्रय के लिए माल के उत्पादन के प्रयोजन के लिए कारबार स्थापित करने के लिए आशयित कोई व्यक्ति, जो उप-धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए जिम्मेदार नहीं है, के होते हुए भी उसे ऐसी शर्तों के अध्वधीन और ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान किया जा सकेगा, और ऐसा व्यक्ति, जब उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र अनुदत्त किया गया हो, जब तक कि ऐसा प्रमाण-पत्र प्रदत्त रहता है, इस अधिनियम के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी होगा:

परन्तु रजिस्ट्रीकरण का ऐसा प्रमाण-पत्र शर्तों के अध्वधीन प्रदान किया जाएगा कि, यदि ऐसा व्यक्ति प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट अबधि के भीतर कारबार स्थापित करने में असफल रहता है या उसमें विनिर्दिष्ट किसी भी शर्त का पालन करने में असफल रहता है तो वह निर्धारण अधिकारी के आदेश द्वारा कर की रकम के आधे के बराबर शास्ति का संदाय करने का दायी होगा, जो उसके द्वारा समस्त माल के क्रय करने पर संदत्त की जाती मानो कि वह इस उप-धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं होता।

(3) उप-धारा (1) द्वारा प्रत्येक व्योहारी जो रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित है और प्रत्येक व्यक्ति जिसे उप-धारा (2) के अधीन प्रमाण-पत्र जारी किया जाना है, वह इस निमित्त विहित रीति में निर्धारण प्राधिकारी को आवेदन करेगा।

(4) यदि निर्धारण प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि उप-धारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए किया गया आवेदन सही है, वह ऐसे नियमों के अनुसार और ऐसी फीस के संदाय पर तथा ऐसी शर्तों के अध्वधीन जैसी विहित की जाएं, आवेदक को रजिस्ट्रीकृत करेगा और उसे विहित प्ररूप में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा।

(5) जब कोई व्यौहारी इस धारा की उप-धारा (1) के उल्लंघन में रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन करने में असफल हो जाता है, तो निर्धारण प्राधिकारी ऐसे व्यौहारी को रजिस्ट्रीकृत करेगा और उसे रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा और ऐसा रजिस्ट्रीकरण ऐसे प्रभावी होगा जैसे यह व्यौहारी के आवेदन पर उप-धारा (4) के अधीन जारी किया जाता ।

(6) निर्धारण प्राधिकारी आदेश द्वारा—

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का संशोधन कर सकेगा—

(क) व्यौहारी के आवेदन पर, यदि व्यौहारी या उसका विधिक प्रतिनिधि यह सूचना देता है कि,—

- (i) उसने अपना कारबार स्थानांतरित कर लिया है, या
- (ii) उसने अपने कारबार का नाम (स्थापना) या स्वरूप बदल लिया है, या
- (iii) कारबार नए स्थान पर खोलना चाहता है या कारबार के स्थान में अथवा अपने रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट पुन. विक्रय हेतु माल या विक्रय हेतु माल विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाले माल के वर्ग या वर्गों में परिवर्तन करना चाहता है ;

(ख) यदि व्यौहारी या व्यक्ति ने, इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों का अतिक्रमण किया है, किसी अन्य शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को कार्यान्वित करना है ;

(ग) यथास्थिति, व्यौहारी उसके विधिक प्रतिनिधि के आवेदन पर अथवा स्व-प्रेरणा से, ऐसे रद्दकरण तक के संदाय के दायित्व को प्रभावित किए बिना, रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र को रद्द कर सकेगा,—

- (i) यदि व्यौहारी अपना कारबार या कारबार के किसी स्थान का विक्रय करता है या उसे अन्यथा व्ययनित करता है या अपना कारबार जारी नहीं रखता है, या
- (ii) यदि व्यौहारी की मृत्यु हो जाती है, या
- (iii) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के दुरुपयोग सहित किसी अन्य पर्याप्त कारण के लिए या इस अधिनियम के अधीन कर के संदाय के दायित्व की समाप्ति हो जाती है :

परन्तु इस उप-धारा के खण्डों (ख) और (ग) के अधीन सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला आदेश नहीं किया जाएगा ; और

(घ) ऐसी प्रवधि के लिए और ऐसी रीति में तथा ऐसी फीस के संदाय पर, जैसी विहित की जाए, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का नवीकरण कर सकेगा ।”

धाराएं 8-क, 9, 10, 10-क, 10-ख और 10-ग का लोप किया जाएगा।  
क, 10-ख,  
और 10-ग  
का लोप।

धारा 12 का संशोधन। 7. मूल अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (4) में,—

(i) “भागीय रिजर्व बैंक” शब्दों के स्थान पर, “अनुसूचित बैंक जो खजाना बैंक है” शब्द रखे जाएंगे, और

(ii) प्रथम परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़े जाएंगे, अर्थात् :—

“परन्तु यह और भी कि जब व्योहारी खजाना बैंक से भिन्न अनुसूचित बैंक द्वारा संदाय करना है, वह ऐसे बैंक से, उस प्रभाव का, जैसा विहित किया जाए, एक प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त करेगा, कि बैंक ने व्योहारी के निदेशों पर कर की रकम खजाना बैंक को भेज दी है और निर्धारण प्राधिकारी को ऐसा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर, उस तारीख की पञ्चाव्वर्ती तारीख को जिसको ऐसे बैंक द्वारा ऐसा प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, व्योहारी द्वारा कर संदत्त किया गया समझा जाएगा।

परन्तु यह और भी कि अनुसूचित बैंक जो खजाना बैंक से भिन्न स्थान पर स्थित है, द्वारा संदाय करने की दशा में, व्योहारी को सम्बद्ध बैंक से विहित प्रमाण-पत्र, जैसा पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन वर्णित है, उप-धारा (3) के अधीन विवरणी दाखिल करने के लिए विहित देय तारीख के अवसान से कम से कम तीन दिन पूर्व, उपाप्त करना आवश्यक होगा और उस दशा में व्योहारी द्वारा देय तारीख को संदाय किया गया समझा जाएगा।”।

धारा 21 का प्रतिस्थापन। 8. मूल अधिनियम की धारा 21 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“21 प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से निर्धारिती को अनुज्ञात करना.—कोई निर्धारिती, व्योहारी या अन्य व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का हकदार है या जिससे उपस्थित होने की अपेक्षा की जाती है, सिवाय जब स्वयं उपस्थित होने की अपेक्षा की जाए, उस निमित्त लिखित रूप में, विहित रीति में, उस द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से उपस्थित हो सकेगा।”।

धारा 25 का लोप। 9. मूल अधिनियम की धारा 25 का लोप किया जाएगा।

धारा 42-ख का संशोधन। 10. मूल अधिनियम की धारा 42-ख के खण्ड (क) में, “कच्ची मामरी” शब्दों के पश्चात् और “के रूप में” शब्दों से पूर्व, “संयंत्र या मशीनरी” चिह्न और शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

**AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT**

**Act No. 21 of 2000.**

**THE HIMACHAL PRADESH GENERAL SALES TAX (SECOND AMENDMENT) ACT, 2000**

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 16TH SEPTEMBER, 2000)

AN

ACT

*further to amend the Himachal Pradesh General Sales Tax Act, 1968 (Act No. 24 of 1968).*

Be it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-first Year of the Republic of India, as follows :—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh General Sales Tax (Second Amendment) Act, 2000.

Short title.

(24 of 1968)

2. In section 4 of the Himachal Pradesh General Sales Tax Act, 1968 (hereinafter called the 'principal Act'),—

Amendment of section 4.

(i) sub-section (1) shall be omitted; and

(ii) for sub-section (2), the following shall be substituted, namely:—

“(2) Every dealer who does not deal exclusively in goods declared to be tax free under section 7 shall be liable to pay tax under this Act from the date on which his gross turnover during any year first exceeds the taxable quantum.”.

3. In section 6 of the principal Act,—

Amendment of section 6.

(i) in sub-section (1), for the first proviso, the following shall be substituted, namely:—

“Provided that a tax at such rate not exceeding 20 paise in a rupee, as may be so notified, may be levied on the sale of goods as specified in Schedule-‘A’ except on—

(a) Lime-stone on which a tax at the rate not exceeding 100 paise in a rupee, and

(b) Liquor (Country Liquor, Foreign Liquor and Indian Made Foreign Liquor including Bear but excluding Indian made cider and wines), Polythene Bags and Timber (but not including converted timber), on which a tax at the rate not exceeding 30 paise in a rupee,

shall be levied:

Provided further that the Government, after giving by notification not less than thirty days notice of its intention so to do, may, by like notification, add to or delete from Schedule-‘A’ any goods, or otherwise amend the Schedule, and thereupon

the Schedule shall be deemed to have been amended accordingly"; and

(ii) in sub-section (3), in clause (a), sub-clause (iii) shall be omitted.

Amendment  
of section 7.

4. In section 7 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "add to or delete from Schedule 'B'", the words and signs "add to or delete from Schedule 'B' any goods or otherwise amend the Schedule," shall be substituted.

Amendment  
of section 8.

5. In section 8 of the principal Act, for sub-sections (2), (3), (4), (5) and (6), the following shall be substituted, namely:—

"(2) Any person intending to establish a business in Himachal Pradesh for the purpose of manufacturing goods for sale may, notwithstanding that he is not liable to registration under sub-section (1), be granted a registration certificate subject to such conditions and in the manner as may be prescribed, and such person when granted a registration certificate shall, for so long as such certificate is in force, be liable to pay tax under the Act :

Provided that grant of such a certificate of registration shall be subject to the conditions that if such person fails to establish the business within the period specified in the certificate or fails to comply with any of the conditions specified therein, he shall be liable by order of the Assessing Authority, to pay a penalty equivalent to one-half of the amount of tax which would have been payable by him in respect of all the goods purchased by him as if he had not been registered under this sub-section.

(3) Every dealer required by sub-section (1) to be registered and every person who may be granted registration certificate under sub-section (2) shall make application in this behalf in the prescribed manner to the Assessing Authority.

(4) If the Assessing Authority is satisfied that an application for registration made under sub-section (3) is in order, he shall, in accordance with such rules and on payment of such fee and subject to such conditions as may be prescribed, register the applicant and grant him a certificate of registration in the prescribed form.

(5) When any dealer fails to apply for registration in contravention of sub-section (1) of this section, the Assessing Authority shall register such dealer and grant him a certificate of registration and such registration shall take effect as if it had been made under sub-section (4) of this section on the dealer's application.

(6) The Assessing Authority may, by order,—

(a) amend certificate of registration on the dealer's application if the dealer or his legal representative furnishes the information that he—

(i) has transferred his business, or



- (ii) has changed the name (constitution) or nature of his business, or
- (iii) wants to open a new place of business or make any change either in the places of business or in the class or classes of goods specified in his certificate of registration for resale or for use in manufacture of goods for sale ;
- (b) suspend a certificate of registration, without prejudice to any other penalty, if the dealer or person has violated any provision of this Act or rules made thereunder;
- (c) cancel a certificate of registration, on dealer's or, as the case may be, of his legal representative's application or *suo-moto*, without affecting liability to pay tax till such cancellation,—
  - (i) if the dealer sells or otherwise disposes of his business or any place of business or discontinues his business, or
  - (ii) if the dealer dies, or
  - (iii) for any other sufficient cause including misuse of the certificate of registration or cessation of liability to payment of tax under this Act;

Provided that no order affecting any person adversely shall be made under clauses (b) and (c) of this sub-section without affording him a reasonable opportunity of being heard; and

- (d) renew a certificate of registration for such period and in the manner and on payment of such fee as may be prescribed.”.

6. Sections 8-A, 9, 10, 10-A, 10-B and 10-C of the principal Act shall be omitted.

Omission of sections 8-A, 9, 10, 10-A, 10-B and 10-C.

7. In section 12 of the principal Act, in sub-section (4),—

Amendment of section 12.

- (i) for the words “Reserve Bank of India”, the words “Scheduled Bank which is a treasury bank” shall be substituted, and
- (ii) after the first proviso, the following provisos shall be added namely:—

“Provided further that when a dealer makes payment through a Scheduled Bank other than the treasury bank, he shall obtain from such bank a certificate, as may be prescribed, to the effect that the bank has remitted the amount of tax to the treasury bank on the dealer's directions and on production of such certificate to the Assessing Authority the dealer shall be deemed to have paid the tax on the date following the date on which such certificate is issued by such bank:

Provided further that in case of payment through a Scheduled Bank which is located at a station other than that of the treasury bank, the dealer shall need to procure the prescribed certificate from the concerned bank, as mentioned under the preceding proviso, at least three days before the expiry of the due date

prescribed under sub-section (3) for filing the return and in that case the dealer shall be deemed to have made the payment by due date.”.

**Substitution of section-21.** 8. For section 21 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

“21. *Assessee etc. permitted to attend through authorized agent.*—

Any assessee, dealer or other person, who is entitled or required to attend before any authority in connection with any proceedings under this Act, except when required to attend in person, may attend through a person authorized by him in writing in this behalf, in the prescribed manner.”.

**Omission of section 25.** 9. Section 25 of the principal Act shall be omitted.

**Amendment of section 42-B.** 10. In section 42-B of the principal Act, in clause (a), after the words “raw material” but before the words “in the manufacture”, the sign and words “, plant or machinery” shall be inserted.